



बढ़ते कर्ज़ से घरेलू बचत पर संकट

प्रलिमिस के लिये:

घरेलू उपभोग वयय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सकल घरेलू उत्पाद, उपभोक्ता मूल्य मुद्रासंकीय, नीति आयोग, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता वयय, सी. रंगाजन समिति

मेन्स के लिये:

हाल के घरेलू उपभोग वयय सर्वेक्षण की मुख्य बातें

स्रोत: द हंडि

हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के मुकाबले अधिक ऋण लेने के कारण वर्ष 2022-23 के दौरान **सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product - GDP)** अनुपात की तुलना में घरेलू नविल बचत में आई गशिष्ट के मुद्रे पर बहस शुरू हुई है।

- भारत सरकार के मुख्य आरथिक सलाहकार (CEA) ने इसकी वयाख्या घरेलू बचत की संरचना में बदलाव मात्र के रूप में की, जहाँ परविरासों को केवल उच्च भौतिक बचत (नविश) के वित्तपोषण के लिये अधिक ऋण लेना पड़ता है।
- हालांकि, कुछ वर्षों असहमत हैं और उनका मानना है कि इस प्रवृत्ति के पीछे केवल लोगों की अत्यधिक खर्च करने की आदतें ही नहीं, बल्कि कई बड़े आरथिक कारण भी हो सकते हैं।

भारत सरकार के मुख्य आरथिक सलाहकार (CEA):

- ये सरकार को आरथिक मामलों पर सलाह देते हैं और भारत का केंद्रीय बजट पेश होने से पूर्वसंसद में पेश किये जाने वाले भारत के आरथिक सर्वेक्षण की तैयारी के लिये ज़मिमेदार होते हैं।
- CEA भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आरथिक मामलों के विभाग के आरथिक प्रभाग का प्रमुख होता है।
- उसके पास भारत सरकार के सचिवि का पद होता है।

नोट:

- घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत: यह घरेलू आय के उस भाग को संदर्भित करता है जो ऋण एवं वित्तीय देनदारियों के बाद बचता है तथा वित्तीय प्रसिद्धतायों, जैसे बैंक जमा, स्टॉक, बॉण्ड तथा अन्य वित्तीय उपकरणों में नविश किया जाता है।
 - यह एक अवधिमें परविरासों द्वारा रखी गई वित्तीय संपत्तियों में शुद्ध प्रविरतन का प्रतनिधित्व करता है।
 - उच्च शुद्ध वित्तीय बचत उच्च आरथिक स्थिरता का संकेत देती है।
- घरेलू बचत और GDP अनुपात: घरेलू बचत और GDP का अनुपात इसकी शुद्ध वित्तीय बचत एवं GDP अनुपात, भौतिक बचत तथा GDP अनुपात व सोने और आभूषणों का योग है।
 - गणतीय अभवियक्ता रूप में: घरेलू बचत = शुद्ध वित्तीय बचत + भौतिक बचत + (स्वरूप और आभूषण)।

बचत पैटर्न में वर्तमान प्रविरतन क्या है?

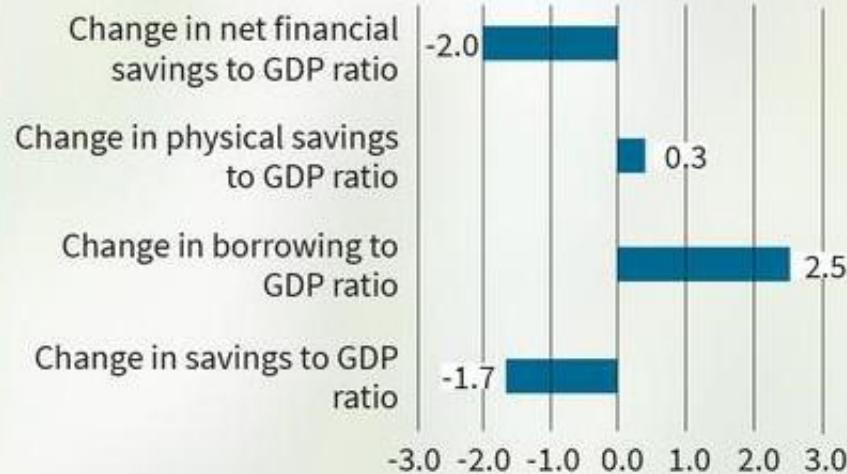
- बढ़ा हुआ उधार और संपत्ति में स्थिरता:
 - अधिक उधारी (2.5% तक) होने से शुद्ध वित्तीय बचत (-2.0% तक) कम हो गई है, लेकिन भौतिक बचत तथा नविश में अधिक वृद्धि (केवल 0.3% तक) नहीं हुई है।
 - यह सरकार के उस दृष्टिकोण का खंडन करता है कि अधिक उधार लेने (शुद्ध वित्तीय बचत में कमी) के कारण भौतिक बचत में

वृद्धि हुई है।

- घरेलू बचत और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 1.7% अंक की गणितीय आई, जबकि सोने की बचत व सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात काफी हद तक अपवाहित रहा।

II

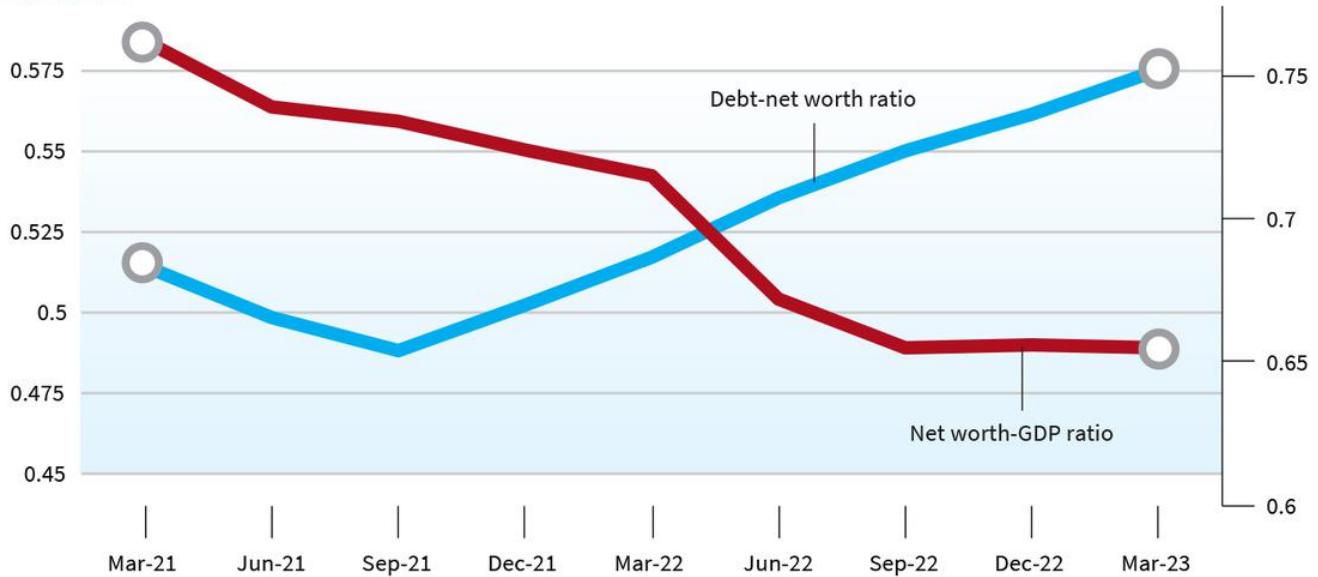
Deciphering trends: Changes in the components of the savings to GDP ratio in FY21-FY23



■ घरेलू वित्तीय संपत्ति और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में गणितीय:

- समग्र अरथव्यवस्था की तुलना में परवार निधन होते जा रहे हैं, साथ ही अधिक धन भी उधार ले रहे हैं। ऐसा इसलिये है क्योंकि घरेलू वित्तीय संपत्ति और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात तेजी से कम हुआ है, जबकि ऋण-से-निवाल-मूल्य अनुपात बढ़ गया है।

Figure 4: Household net worth GDP ratio and debt-net worth ratio



■ ब्याज भुगतान बोझ, कसी निधारति ब्याज दर पर, ब्याज दर और ऋण-आय (DTI) के अनुपात का उत्पाद है।

- ब्याज भुगतान बोझ में वृद्धि: ब्याज भुगतान का बोझ कसी निधारति ब्याज दर पर, ब्याज दर और ऋण-आय (DTI) के अनुपात का उत्पाद है।

- ऋण-से-आय (Debt-To-Income- DTI) अनुपात एक वृत्तीय अनुपात है जो उधारकर्ता के कुल मासिक ऋण की तुलना उनकी कुल मासिक आय से करता है।
 - उच्च ऋण-से-आय अनुपात इंगति करता है कि किसी व्यक्तिको अपने ऋणों पर चूक का जोखमि हो सकता है, जबकि निम्न अनुपात दर्शाता है कि उनके पास अपने ऋण दायतिवों को कवर करने के लिये अधिक प्रयोज्य आय (Disposable Income) है।
 - हाल की अवधि इन दोनों चर (DTI और ब्याज भुगतान) में तीव्र वृद्धि से संबंधित है।
 - परविरों का ऋण-आय अनुपात दो कारकों के कारण परविरति हो सकता है।
 - उच्च शुद्ध उधार-आय अनुपात, जहाँ कुल उधार और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है।
 - यदि परविर उच्च नविश या उपभोग के वित्तपोषण को बढ़ाने का निश्चय लेता है।
 - ब्याज दरों में वृद्धिया नाममात्र आय (Nominal Income) वृद्धिदर में कमी।
 - यदि ब्याज भुगतान में वृद्धिआय वृद्धिसे अधिक है, तो ऋण-आय अनुपात बढ़ता रहेगा। ऐसे तंत्रों को "फशिर डायनेमिक्स" (ब्याज दर और नाममात्र आय वृद्धिदर में परविरतन के संदर्भ में बढ़ते ऋण-आय अनुपात की घटना) के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- घरेलू आय वृद्धिउधार दर से पीछे:
 - 2019-20 से 2022-23 की अवधि के लिये घरेलू प्रयोज्य आय की वृद्धिदर का औसत मूल्य (2019-20 से 2021-22 में 8% और 2019-20 से 2022-23 में 9.3%) भारती औसत उधार दर (Weighted Average Lending Rate- WALR) (2019-22 में 9.3% और वर्ष 2019-23 में 9.4%) से कम रहा है।
 - इस अवधि के लिये उधार दर का औसत मूल्य भारतीय रजिस्टर बैंक के तमाही ऑफिसों द्वारा तय किया गया है।

Lending rate and the household GDI growth (%)		
	2019-20 to 2021-22	2019-20 to 2022-23
Avg. lending rate (RBI)	9.3	9.4
Average household GDI [^] growth rate	8.0	9.3
Average household GDI growth rate minus Average WALR*	-1.3	-0.1

- 2003-08 और 2019-22 के बीच बचत और नविश में गरिवट:
 - वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक औसत सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income- GNI) वृद्धिदर (14.5%) औसत उधार दर (11.5%) से अधिक थी।
 - इसका तात्पर्य यह था कि आय उधार लेने की लागत की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही थी।

Lending rate and the GNI growth (%)		
	2003-04 to 2007-08	2019-20 to 2021-22
Average Lending rate (IMF)	11.8	8.8
Average GNI** growth rate	14.5	8.7
Average GNI growth rate minus Avg lending rate	2.7	-0.1

- फशिर डायनेमिक्स 2019-20 से सक्रिय है:
 - यह ब्याज दर और नाममात्र आय में परविरतन के कारण ऋण-आय अनुपात बढ़ने की घटना है।

- वर्ष 2019-20 में आरथकि मंदी के बाद से, भारतीय अरथव्यवस्था ने फशिर डायनेमिक्स के संकेत दिखाए हैं।
- कोविड-19** के बाद, परविरांगों की आय की तुलना में ऋण की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण नाममात्र (Nominal) की आय वृद्धि दिर है।
- मछुआरों की गतशीलता के उदय के साथ, भारतीय अरथव्यवस्था के समक्ष 2 महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं:
 - बढ़ता आय-ऋण अंतर:** इससे परविरांगों को अधिक ब्याज भुगतान करना पड़ सकता है।
 - न्यूनतम खपत:** अधिक ऋण परविरांगों को खरच में कटौती करने के लिये प्रेरित करता है। वर्ष 2023-24 में खपत और GDP अनुपात में गरिवट आई, जो इस प्रवृत्ति को दर्शाता है।

बढ़ते घरेलू ऋण बोझ के व्यापक आरथकि नहितिरथ क्या हैं?

- ऋण अदायगी:** यदि आय वृद्धि की तुलना में ब्याज दरें तेजी से बढ़ती हैं तो यह चुनौतीपूरण हो सकता है इससे वित्तीय क्षेत्र पर दबाव पड़ सकता है क्योंकि उन्हें ऋण अदायगी के लिये संघर्ष कर रहे परविरांगों से न्यूनतम ब्याज आय प्राप्त होती है। इसके परणामस्वरूप व्यवसायों के लिये ऋण उपलब्धता कम हो सकती है।
- उपभोग मांग:** इसे उच्च घरेलू ऋण द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। यदि परविरांग आरथकि रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वे अधिक बचत कर सकते हैं और खरच में कमी कर सकते हैं, जिससे समग्र अरथव्यवस्था धीमी हो जाएगी।
- मुद्रास्फीति से बचाव हेतु उच्च ब्याज दर:** यदि मुद्रास्फीति से नपिटने के लिये ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं, तो इससे घरेलू ऋण का बोझ बढ़ सकता है और वे ऋण जाल से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसा इसलिये होगा क्योंकि उच्च ब्याज दरें होने से परविरांग द्वारा अपने ऋणों के लिये भुगतान की जाने वाली धनराशमें वृद्धि होती है।
- अरथव्यवस्था का वित्तीयकरण:** घरेलू बैलेंस शीट में वित्तीय परसिंपत्तयों की ओर बदलाव से पता चलता है कि अरथव्यवस्था अधिक वित्तीय होती जा रही है। इसका तात्पर्य है कि आरथकि गतिविधि का एक बड़ा हिस्सा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बजाय वित्तीय बाज़ारों पर केंद्रित है। यह अरथव्यवस्था को अधिक नाजुक और वित्तीय संकटों के लिये प्रवण बना सकता है।
- वित्तीयकरण उन अरथव्यवस्थाओं में एक प्रवृत्ति को संदर्भित करता है जहाँ वित्तीय बाज़ार उत्पादन पर प्राथमिकता लेते हैं, जहाँ व्यक्तिगत संचय करने के लिये स्टॉक और बॉण्ड जैसी वित्तीय संपत्तयों की ओर रुख करते हैं।**

आगे की राह

- आय वृद्धि और ऋण नियंत्रण पर ध्यान देना:** ब्याज दरों और आय वृद्धि के बीच अंतर को कम करने की आवश्यकता है और आय की तुलना में घरेलू ऋण की वृद्धि को धीमा करने की आवश्यकता है।
- आय वृद्धि को बढ़ावा देना:** रोज़गार सृजन, वेतन वृद्धि और समग्र आरथकि विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ एवं पहल महत्वपूरण हैं।
- ऋण स्तर का प्रबंधन:** उचित ऋण प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और संभावित रूप से अत्यधिक उच्च ऋण दरों को विनियमित करने से, परविरांगों को ऋण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता मिल सकती है।
- वेतन वृद्धि:** यदि वेतन में वृद्धि, ब्याज दरों में होने वाली वृद्धि से अधिक है, तो परविरांगों के पास ऋण का प्रबंधन करने और संभावित रूप से अधिक खरच करने के लिये अधिक प्रयोज्य आय होगी।
- ऋण प्रबंधन रणनीतियाँ:** वित्तीय शक्तिशाली पहल और उचित ऋण देने की प्रथाएँ परविरांगों को ऋण को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता कर सकती हैं, जिससे खरच के लिये कुछ आय शेष रह जाती है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

भारत की घरेलू वित्तीय संपत्तयों में गरिवट और उधार लेने की बढ़ती लागत पर चर्चा की जाय। इस प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाली संभावित व्यापक आरथकि चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये और उनसे नपिटने हेतु नीतिगत उपाय प्रस्तावित कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्षों के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. एन.एस.एस.ओ. के 70वें चक्र द्वारा संचालित "कृषक-कुटुम्बों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण" के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

- राजस्थान में ग्रामीण कुटुम्बों में कृषक-कुटुम्बों का प्रतिशत सर्वाधिक है।
- देश के कुल कृषक-कुटुम्बों में 60% से कुछ अधिक ओ.बी.सी. के हैं।
- केरल में 60% से कुछ अधिक कृषक-कुटुम्बों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषक स्रोतों से प्राप्त की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 2 और 3
(b) केवल 2

- (c) केवल 1 और 3
(d) 1,2 और 3

उत्तर: c

प्रश्न. कसी दिये गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि (2019)

- (a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है,
(b) कीमत-स्तर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है,
(c) सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है,
(d) सार्वजनिक वितरण की गुणता अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है,

उत्तर: (b)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rising-debt-strained-household-savings>

